साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

दि कार्मिक पोस्ट

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 7, अंक : 40 (प्रति बुधवार), इन्दौर 25 मई 2022 से 31 मई 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा दिल्ली में 20 झीलों का विकास, पर्यावरण मंत्री ने बताई पूरी प्लानिंग...

नई दिल्ली। झीलों के विकास के संबंध में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में संबंधित एजेंसियों की बैठक हुई। बैठक में दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसायटी (डीपीजीएस), वेटलैंड अथारिटी आफ दिल्ली, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों, लैंड आनिंग एजेंसीज, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के बाद गोपाल राय ने बताया कि पहले चरण में दिल्ली की 20 झीलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पुनर्जीवित, विकसित और संरक्षित करने का निर्णय लिया गया। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि वेटलैंड अथारिटी और पर्यावरण विभाग ने कुल 1045 में से करीब 1018 झीलों की मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया है। इन 1045 झीलों को यूआईडी नंबर भी आवंटित कर दिए गए हैं। आगे इसी परियोजना के आधार पर बाकी झीलों का भी विकास किया जाएगा।उन्होंने बताया कि पहले चरण की 20 झीलों में संजय झील, हौजखास झील, भलस्वा झील, स्मृति वन (कुंडली), स्मृति वन (वसंत कुंज), टिकरी खुर्द झील, नजफगढ़ झील, वेलकम झील, दर्यापुर कलां झील, पुठ कलां (सरदार सरोवर झील), मुंगेशपुर, धीरपुर, संजय वन का एमपी ग्रीन एरिया, अर्वतिका सेक्टर- एक रोहिणी के जिला पार्क, बरवाला, वेस्ट विनोद नगर (मंडावली, फजलपुर), मंडावली गांव, राजौरी गार्डन, बरवाला और झटिकरा की झीलें शामिल हैं। गोपाल राय ने बताया कि झीलों को पुनर्जीवित के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उन झीलों से संबंधित शिकायतों पर कार्य किया जाए। अभी तक की आई रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण, सीवेज डिस्चार्ज और ठोस कचरे की डंपिंग मुख्य समस्या के तौर पर देखी गई हैं। इन समस्याओं के निवारण और झीलों के विकास के लिए जिलास्तरीय शिकायत निवारण कमेटी गठित की गई है, जो समय-समय पर इन झीलों की निगरानी और निरीक्षण करेंगी। साथ ही झीलों से संबंधित शिकायतें निपटाएंगी।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया- दिल्ली की आबोहवा को बेहतर बनाने के लिए किस मिशन का किया गया शुभारंभ

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पार्क सौन्दर्यीकरण योजना के तहत दिल्ली के पार्कों का सौन्दर्यीकरण ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली की थीम पर करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए हर विधानसभा में एक इंचार्ज , हर दो विधानसभा पर एक पर्यवेक्षक और राज्य स्तर पर दो समन्वयकों की प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति की जा रही है। इस आशय का निर्णय सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई एक बैठक में लिया गया।

इस बैठक में विधायक एवं आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान आरडब्ल्यूए को योजना में शामिल करने की आनलाइन प्रक्रिया एवं दस्तावेजों की जानकारी भी साझा की गई। विधायकों को उनके एरिया में मौजूद पार्कों के बारें में विस्तृत जानकारी भी दी गई। बैठक के बाद प्रेसवार्ता में गोपाल राय ने बताया कि अभियान के पहले चरण में दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसायटी (डीपीजीएस) की 70 टीमों द्वारा दिल्ली के 16 हज़ार 828 पार्कों में से लगभग 11 हज़ार 500 पार्कों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। इनमें लगभग छह हज़ार 345 पार्क अच्छी स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पार्कों के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए प्रत्येक आरडब्लूए को डीपीजीएस द्वारा प्रति एकड़ दो लाख 55 हज़ार की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही नए पार्कों के विकास के लिए प्रति एकड़ एक लाख की अतिरिक्त धनराशि भी देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पार्कों में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाने के लिए प्रति एकड़ तीन लाख 50 हज़ार की सहायता देने का निर्णय भी लिया गया है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि आरडब्लूए इस योजना में एक एप्लीकेशन के द्वारा आवेदन कर सकती हैं। इसके अनुसार सबसे पहले उन्हें अपने आसपास के किसी पार्क का चुनाव करना हैं, इसके बाद पार्क अपनाने के लिए पंजीकृत आरडब्लूए होना अनिवार्य है। यदि कोई पंजीकृत आरडब्लूए मौजूद ना हो तो नई आरडब्लूए बनाएं और पंजीकृत कराएं। इसके बाद आरडब्लूए अपनी पात्रता की जांच करे। पात्रता/ योग्यता की जांच के बाद उन्हें दिल्ली सरकार के ई- जिला पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा और साथ ही सभी उल्लेखित दस्तावेज़ों को अपलोड करना भी अनिवार्य हैं।

सम्पन्न देशों में संसाधनों की अति-खपत, बच्चों के स्वास्थ्य पर जोखिम

सूडान संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि अधिकांश सम्पन्न देशों में संसाधनों का उपभोग अधिक होने से, विश्व भर में बच्चों के लिये अस्वस्थ, खतरनाक व हानिकारक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं. यूनीसेफ़ ने बच्चों के स्वास्थ्य व पर्यावरण की रक्षा व उनके लिये बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिये सुझाव प्रस्तुत किये हैं.

यूनीसेफ़ के शोध कार्यालय की नवीनतम रिपोर्ट 'Innocenti Report Card v|: Places and Spaces' में, बच्चों के लिये स्वस्थ पर्यावरण के विषय में, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन और योरोपीय संघ के 39 देशों में हालात का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है. अध्ययन के अनुसार, यदि विश्व में हर एक व्यक्ति OECD समूह और योरोपीय देशों की दर से संसाधनों की खपत करे, तो उपभोग का मौजूदा स्तर बनाए रखने के लिये 3.3 पृथ्वी जैसे तीन ग्रहों की ज़रूरत होगी. मगर, यदि यह खपत कैनेडा, लक्ज़मबर्ग और अमेरिका में मौजूदा जीवन शैली के स्तर पर की जाती है, तो कम से कम पाँच पृथ्वियों की आवश्यकता होगी. यूनीसेफ़ शोध कार्यालय की निदेशक गुनीला ओलस्सन ने बताया कि, ÷अधिकांश धनी देश ना सिर्फ़ अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिये स्वस्थ माहौल प्रदान करने में विफल हो रहे हैं, बल्कि वे दुनिया के अन्य हिस्सों में, बच्चों के पर्यावरण को तबाह करने में भी योगदान दे रहे हैं.÷

वैश्विक पर्यावरण पर प्रभाव- यह रिपोर्ट तैयार करने के लिये, ज़हरीली हवा, कीटनाशक, सीसा; प्रकाश, हरित स्थलों जैसे नुक़सानदेह प्रदूषकों और सुरक्षित मार्गों की सुलभता; जलवायु संकट में देशों का योगदान; संसाधनों की खपत और ई-कचरे जैसे संकेतकों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है. इसके अनुसार, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कैनेडा और अमेरिका समेत अन्य अति-सम्पन्न देशों का, वैश्विक पर्यावरण पर गम्भीर और व्यापक असर पड़ा है. इस प्रभाव को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, ई-कचरा और प्रति व्यक्ति संसाधनों की खपत से आँका गया है. साथ ही, ये देश अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिये स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण की सूची में निचले स्थान पर हैं. इसके विपरीत, OECD समूह और योरोपीय संघ में सबसे कम सम्पन्न देशों का शेष जगत पर कहीं कम असर है। कुल मिलाकर, इस सूची में स्पेन, आयरलैण्ड और पुर्तगाल शीर्ष देशों में हैं, लेकिन हश्चष्ठ समूह और योरोपीय संघ के सभी देश, सभी संकेतकों पर बच्चों को स्वस्थ पर्यावरण दे पाने में विफल हो रहे हैं। यूनीसेफ़ शोध कार्यालय निदेशक ने बताया कि कुछ देश अपने यहाँ बच्चों के लिये अपेक्षाकृत स्वस्थ पर्यावरण तो सुनिश्चित कर पाए हैं, लेकिन वो उन प्रदूषकों के लिये ज़िम्मेदार देशों की सूची में शीर्ष पर हैं, जिनसे विदेश में बच्चों के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है।

रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष- इस समूह के देशों में दो करोड़ से अधिक बच्चों के रक्त में सीसा की मात्रा अधिक पाई गई है, जोकि एक ख़तरनाक विषैला पदार्थ है. फ़िनलैण्ड, आइसलैण्ड और नॉर्वे अपने यहाँ बच्चों को एक स्वस्थ माहौल प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर हैं, मगर उत्सर्जन की ऊँची दर, ई-कचरे और खपत के विषय में दुनिया में वे निचले स्थान पर हैं. बड़ी संख्या में बच्चे अपने घरों में और बाहर, विषैली हवा में साँस ले रहे हैं. वायु प्रदूषण के कारण, स्वस्थ जीवन के वर्षों को खो देने में मैक्सिको सबसे ऊपर है, जहाँ प्रति हज़ार बच्चों में 3.7 वर्ष का नुक़सान होता है. जबकि फ़िनलैण्ड और जापान के लिये यह आँकड़ा बेहद कम, 0.2 वर्ष है.

जर्मनी के कोलोन शहर में एक ऊर्जा संयंत्र से उत्सर्जन- बेल्जियम, चैक गणराज्य, इसराइल, नैदरलैण्ड्स, पोलैण्ड और स्विट्ज़रलैण्ड में हर 12 में से एक से अधिक बच्चा, ज़्यादा कीटनाशक प्रदूषण की चपेट में हैं. इसे कैंसर समेत अन्य बीमारियों की वजहों से जोड़ कर देखा जाता है. यूनीसेफ़ ने बच्चों के लिये स्वस्थ माहौल के निर्माण हेतु देशों की सरकारों से अहम उपाय अपनाने का आग्रह किया है.

बेहतरी के लिये सुझाव- इस क्रम में, कचरे, वायु व जल प्रदूषण में कमी लाना और उच्च-गुणवत्ता वाली आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करना ज़रूरी होगा. सबसे निर्बल बच्चों के रहन-सहन के लिये बेहतर परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, धनी परिवारों की तुलना में निर्धन परिवारों के बच्चों के पर्यावरणीय हानि की चपेट में आने का जोखिम अधिक होता है. इसके अलावा, पर्यावरणीय नीतियाँ तैयार करते समय बाल ज़रूरतों का ध्यान रखे जाने, अभिभावकों व राजनेताओं के परिप्रेक्ष्य को सुनने और भावी पीढ़ियों को प्रभावित करने वाली नीतियों में उनके सुझावों को समाहित किया जाना होगा. रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों को भविष्य के मुख्य हितधारक के रूप में इन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना होगा, जिन्हें लम्बे समय तक मौजूदा पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने के लिये मजबूर होना पड़ सकता है. देशों और व्यवसायों से वर्ष 2050 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती लाने के संकल्प पूरे करने का आग्रह किया है. साथ ही, शिक्षा से लेकर बुनियादी ढाँचे तक, अनुकूलन को जलवायु कार्रवाई के केन्द्र में रखा जाना होगा.

वेस्ट मटेरियल से तैयार की सीमेंट, सस्ती होने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी होगा

भोपाल। मैनिट के कैमेस्ट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉ. सविता दीक्षित व मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. गजेंद्र दीक्षित ने सीमेंट का विकल्प तैयार किया है। इसे भारत सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है। इसे सिलिकॉन, मार्बल पाउडर डस्ट, फ्लाई ऐश और जीजीबीएस मिलाकर तैयार किया गया है। इससे बने पेबर ब्लॉक की उम्र करीब 10 साल होगी। इन्हें पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्किंग में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वेस्ट मटेरियल से तैयार इस सीमेंट से पर्यावरण का संरक्षण करने में भी मदद मिलेगी। दोनों प्रोफेसर ने इसके लिए करीब पांच साल पहले रिसर्च शुरू की थी और दो साल पहले पेंटेंट के लिए अप्लाई किया था। डॉ. दीक्षित का कहना है कि हमारे देश में तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा है, साथ ही आबादी बढ़ने से नए भवनों का निर्माण भी बढ़ गया है। इससे हर साल सीमेंट की खपत भी बढ़ती जा रही है। नेचरल रिसोर्सेस सीमित होने से इसका उत्पादन सीमित है। हमने देखा कि कई इंडस्ट्री ऐसी हैं, जिनसे निकलने वाले वेस्ट को नष्ट करना बेहद खर्चीला है, उनका उपयोग नहीं होने से ये कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने रिसर्च शुरू की कि इन वेस्ट मटेरियल से बना प्रोडक्ट सीमेंट की तरह कितना टिकाऊ हो सकता है। रिसर्च में इसे मिलाना कारगर साबित हुआ, इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। डॉ. गजेंद्र ने बताया कि सीमेंट में इसे करीब 30 फीसदी तक मिलाया जा सकेगा। परीक्षण में यह भी पता चला कि सिलिकॉन, फाइबर, जीजीबीएस, फ्यूम्स आदि से बने कंक्रीट ईंटों की गुणवत्ता व शक्ति, सीमेंट से बने कंक्रीट ईंटों के मुकाबले ज्यादा है। इसके निर्माण की लागत भी कम है। तीन साल तक शोध के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सीमेंट में इन्हें मिलाया जा सकता है। इससे सीमेंट का उत्पादन भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को खपाकर प्रकृति को भी संरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खत्म करेगा क्षेत्रीय कार्यालय वाला कल्चर, गुना, देवास व कटनी जिले से शुरुआत

भोपाल अब लोगों की पहुंच के लिए जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के दफ्तर खुलेंगे। पीसीबी ने पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती जरूरतों व खतरों को देखते हुए यह निर्णय लिया है, ताकि नजदीक से पर्यावरण मामलों पर नजर रखी जा सकें और इन दफ्तरों तक लोगों की पहुंच भी आसान हो सके। इसकी शुरुआत कटनी, गुना व देवास जिलों से हो चुकी है। इन जिलों में अब तक पीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय थे, जिन्हें बंद करके जिला कार्यालयों में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका फायदा आम आदमी और पर्यावरण को होगा।

अभी पीसीबी के चैयरमैन अनिरुद्ध मुखर्जी है। यह बोर्ड पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आता है। विभाग के प्रमुख सचिव भी मुखर्जी ही हैं। उन्होंने पीसीबी का नया खाका खींच दिया है। सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालयों को खत्म करने की शुरुआत की। पूर्व में 16 क्षेत्रीय कार्यालय थे, इनमें से तीन कार्यालयों को बंद कर दिया है, जिसके बाद अब 13 क्षेत्रीय कार्यालय धार, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, मंडीदीप, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, शहडोल, सिंगरौली, ग्वालियर ही बचे हैं। इसी तरह पूर्व में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर व जबलपुर में चार आंचलिक कार्यालय थे। अब मप्र को दो जोन पूर्व और पश्चिम में बांट दिया है इसलिए दो आंचलिक कार्यालय ही बचे हैं। जिलों में कलेक्टर कार्यालय खोलने के लिए पीसीबी ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि कलेक्टर परिसर में दो कमरे उपलब्ध कराएं जाएं। ये कमरे कटनी, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी समेत आसपास के 17 जिलों के लिए मांगे हैं।

जलवायु परिवर्तन- एक ही नाव पर सवार हैं भारत-पाकिस्तान, 30 गुना तक बढ़ गया है गर्मी का कहर

मुंबई। भारत-पाकिस्तान के बीच आपस में चाहे कितने भी मतभेद हों लेकिन जलवायु परिवर्तन के मामले में दोनों ही देश एक ही नाव पर सवार हैं। हाल ही में दोनों देशों में बढ़ती गर्मी और लू को लेकर अंतराष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक एट्रिब्यूशन रिसर्च से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन ने भारत और पाकिस्तान में भीषण गर्मी की आशंका को 30 गुना तक बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं गर्मी की यह लहर समय से पहले ही दोनों देशों को लम्बे समय के लिए अपनी चपेट में ले रही है।

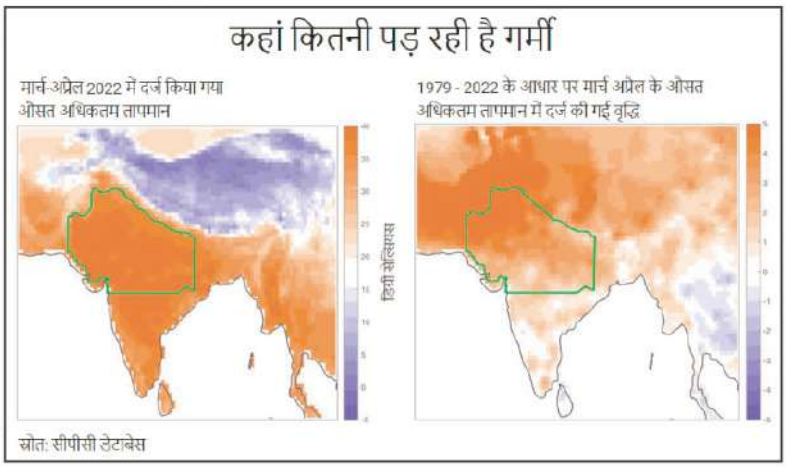

इतना है नहीं रिपोर्ट के अनुसार यदि वैश्विक तापमान में होती वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाती है तो भविष्य में 2022 में पड़ रही भीषण गर्मी और लू जैसी घटनाओं की आशंका और 20 गुना तक बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि भारत, पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में मार्च से ही भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसका कहर अभी भी जारी है। बढ़ते तापमान का ही नतीजा है कि इस साल भारत ने अपने इतिहास का सबसे गर्म मार्च का महीना दर्ज किया था, जब तापमान सामान्य से 1.86 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह पाकिस्तान में भी इस साल मार्च का महीना पिछले 60 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म था। इतना ही नहीं बारिश के मामले में इस साल मार्च का महीना ज्यादा सूखा था। जहां इस साल पाकिस्तान में मार्च के दौरान सामान्य से 62 फीसदी कम बारिश हुई थी वहीं भारत में भी सामान्य से 71 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई। नतीजन परिस्थितियां भीषण गर्मी और लू के लिए अनुकूल बन गई थी। आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट से भी पता चला है कि दक्षिण एशिया में इस सदी के दौरान लू का प्रकोप पहले से कहीं ज्यादा रहने की आशंका है। ऊपर से बढ़ती आद्रता के चलते तापमान व गर्मी का एहसास कहीं ज्यादा होगा। नतीजन परिस्थितियां भीषण गर्मी और लू के लिए अनुकूल बन गई थी। यही वजह थी कि भारत में लू का कहर अप्रैल में भी जारी था और वो महीने के अंत तक अपने चरम पर पहुंच गया था। गौरतलब है कि 29 अप्रैल तक भारत का 70 फीसदी हिस्सा लू से प्रभावित था। वहीं अप्रैल के अंत और मई में लू का कहर तटीय क्षेत्रों और भारत के पूर्वी हिस्सों में भी महसूस किया गया था। हालांकि यह शुरूआती, लंबी और शुष्क गर्मी थी जो सदी की शुरुआत में घटने वाली लू की घटनाओं से बिलकुल अलग हैं। देखा जाए तो मानसून से पहले देश में लू का कहर असामान्य नहीं है। लेकिन इसका इतने लम्बे समय तक रहना सामान्य नहीं है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जलवायु में आता बदलाव मानसून से पहले की गर्मी की तीव्रता को और बढ़ा रहा है। इस बारे में ब्रिटेन के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान में होती वृद्धि ने उत्तर-पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की सम्भावना को 100 गुना तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के लिए जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि इस बार प्रचंड गर्मी का दौर 7 मई से शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान के जकोबाबाद और सिबी में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं 11 मई को एक बार फिर से जकोबाबाद में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बारे में यूके मौसम विभाग से जुड़े मौसम विज्ञानी निक सिल्कस्टोन का कहना है कि साल के इस समय में यह तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। भारत सरकार ने भी अपनी एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा है कि 1951 से 2015 के बीच भारत में भीषण गर्मी की आवृति बढ़ी है। साथ ही पिछले 30 वर्षों में इसमें कहीं ज्यादा वृद्धि देखी गई है। तापमान में होती वृद्धि का सीधा असर दोनों ही देशों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला है कि लू और भीषण गर्मी ने अब तक भारत-पाकिस्तान में 90 लोगों की जान ले ली है। वहीं एक तरफ बढ़ता तापमान और बारिश की कमी ने लोगों के स्वास्थ्य और कृषि पर भी व्यापक असर डाला है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसके चलते पैदावार में करीब 10 से 35 फीसदी की कमी की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं गर्मी के कहर का असर लोगों के स्वास्थ्य को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल तक में भर्ती होना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बढ़ती गर्मी के चलते उत्तरी पाकिस्तान में हिमनद झील के कारण आकस्मिक बाढ़ आ गई थी। वहीं भारत में जंगल में लगने वाली आग की घटनाओं में भी वृद्धि दर्ज की गई थी। गर्मी ने भारत में गेहूं की पैदावार को कम कर दिया था जिसकी वजह से सरकार को उसका निर्यात बंद करना पड़ा था। इसी तरह देश में कोयले की कमी के चलते कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई थी, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। देखा जाए तो दोनों ही देशों में एक बड़ी आबादी को अपनी जीविका के लिए बाहर खुले में काम करना पड़ता है, बढ़ती गर्मी उनकी उत्पादकता और स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है। नतीजन उनकी मजदूरी में कमी आ रही है। भारत में तो बढ़ती गर्मी और लू के चलते कही राज्यों में बच्चों के स्कूल तक जल्द बंद करने पड़ गए थे। इतना है नहीं स्ट्रीट वेंडर, निर्माण, मजदूर, ट्रैफिक पुलिस और खेतों में काम कर रहे किसानों के लिए यह गर्मी कहीं ज्यादा जानलेवा हो सकती है। देखा जाए तो आने वाले समय में बढ़ते तापमान के साथ लम्बे समय तक चलने वाली लू और भीषण गर्मी का कहर आम होता जाएगा। नतीजन कुछ क्षेत्रों में परिस्थितियां जीवन के प्रतिकूल होती जाएंगी। ऐसे में इससे बचने के लिए हमें पहले ही तैयार रहना होगा। हम सिर्फ यह मानकर नहीं रह सकते कि गर्मी के इन प्रभावों को टाला नहीं जा सकता। यदि सही समय पर सही कदम उठाए जाएं तो हम इसके बढ़ते प्रभावों को कम कर सकते हैं। इसमें हीट एक्शन प्लान, प्रारंभिक चेतावनी और कार्रवाई से लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना तक शामिल हैं।

50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनेगा सिटी फारेस्ट, सुरक्षित होगा पर्यावरण

इटावा शहर में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पर्यावरण देने के उद्देश्य से सरकार ने सिटी फारेस्ट योजना लांच की है। इस योजना को अगले छह माह में विकसित कर दिया जाएगा। इटावा शहर के पास फिशर वन फारेस्ट में 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिटी फारेस्ट विकसित किया जाएगा। यहां पर फारेस्ट तैयार होने के साथ-साथ लोगों को नेचुरल पिकनिक स्पाट भी मिल सकेगा। योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा धन जारी किया जा रहा है।

नगर वन योजना में स्मृति वन, आरोग्य और नक्षत्र वाटिकाएं, हरीशंकरी वाटिका बनाई जाएगी। जैव विविधता के लिए इसमें सभी प्रकार के सजावटी झाड़ियां, बेलदार, औषधीय पौधे, फूलों व सब्जी के पौधे लगाए जाएंगे। यहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स, साइकिल ट्रैक, पाथवेज, ओपन जिम, बेंच सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। सिटी फारेस्ट जहां लोगों के फेफड़ों को सुरक्षित रखेंगे वहीं शहरों को जलवायु परिवर्तन से बचाएंगे। इस योजना के लिए केंद्र सरकार दो करोड़ रुपये की धनराशि देगी। जिससे इसको विकसित किया जाएगा। परियोजना में दो लाख 25 हजार पौधे लगाए जाएंगे। पौधों को इस तरीके से लगाया जाएगा कि एक साथ उनका समूह दिखाई देगा। आम, पाकड़, नीम, कटहल, गुलमोहर इत्यादि लगाए जाएंगे। बढ़पुरा रेंज के रेंजर अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सफारी पार्क के फिशर वन फारेस्ट का चयन सिटी फारेस्ट योजना के लिए किया गया है। यहां पर जल्द ही कार्य शुरू होगा। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नगर वन योजना के तहत सामाजिक वानिकी लखना द्वारा रेंज परिसर में वन ब्लाक परिसर 50 हेक्टेयर जगह में बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जिसकी स्वीकृत मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होगा। जिसमें तालाब के निर्माण सहित अन्य कार्य होंगे। जिससे आसपास कस्बा व क्षेत्र के लोग पहुंचकर आनंद ले सकेंगे। जिले के वन विभाग अधिकारी अतुलकान्त शुक्ला के निर्देशन में सामाजिक वानिकी लखना के वन क्षेत्राधिकारी विवेकानन्द दुबे द्वारा शासन द्वारा चलाई जा रही नगर वन योजना योजना के तहत लखना रेंज परिसर में वन ब्लाक परिसर 50 हेक्टेयर जगह में बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसमें एक तालाब का निर्माण होगा व पार्क बनेगा। साथ ही सुगंधित फूलों के पौधों को लगाया जाएगा एवं ओवरहेड वाटर टैंक का भी निर्माण होगा। इसके साथ फव्वारा, सब्समर्सिबल, बैठने के लिए बेंच, पेयजल आपूर्ति के लिए हैंडपंप व सुलभ शौचालय एवं रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी।

बायोक्रस्ट को नुकसान के चलते वातावरण में उत्सर्जित हो सकती है 15 फीसदी ज्यादा धूल

मुंबई।अंतराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के एक टीम द्वारा किए अध्ययन से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जिस तरह बायोक्रस्ट को नुकसान हो रहा है, उसके कारण अब के मुकाबले 2070 तक वातावरण में करीब 15 फीसदी ज्यादा धूल उत्सर्जित हो सकती है। देखा जाए तो बायोक्रस्ट जिसे फ्पृथ्वी की जीवित त्वचाफ्र भी कहा जाता है, भूमि के वो क्षेत्र हैं जो शुष्क तो हैं, पर रेतीले नहीं हैं। यह धरती की वो ऊपरी परत है जिसमें गैर-संवहनी पौधें, सूक्ष्मजीव और लाइकेन यानी काई पाई जाती है। यह सभी जैविक पदार्थ मिट्टी में मिलकर सख्त हो जाते है और एक परत का निर्माण कर देते हैं, जिसकी वजह से धूल के कण वातावरण में नहीं उड़ पाते। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह बायोक्रस्ट एक तरह से धरती की जीवित त्वचा जैसी है, जो धरती का करीब 12 फीसदी तक हिस्सा कवर करती है।

जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित अपने इस शोध में वैज्ञानिकों ने इस धूल से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि यह बायोक्रस्ट वैश्विक धूल चक्र को कैसे प्रभावित करती है। साथ ही जैसे-जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है उसके चलते बायोक्रस्ट को होते नुकसान के भविष्य में क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। गौरतलब है कि अप्रैल 2022 की शुरुआत से ही मध्य पूर्व के कई देशों जैसे ईरान, सऊदी अरब, बहरीन और इराक में धूल के कई भीषण तूफान आए हैं, जिनकी वजह से वहां कई शहरों में स्कूल, कार्यालय बंद करने पड़े थे। इतना ही नहीं पिछले सप्ताह आए दो तूफानों से तो स्थिति इतनी ज्यादा बदतर हो गई थी कि लोगों को सांस की तकलीफ शुरू हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल तक में भर्ती करना पड़ा था। अगस्त 2021 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में धूल के तूफान से होने वाले नुकसान को लेकर जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग रेत और धूल भरी आंधी के चलते खराब होती वायु गुणवत्ता के संपर्क में है। इतना ही नहीं तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान की करीब 80 फीसदी आबादी पर इसका खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट से पता चला है कि 2019 में इन जगहों पर करीब 6 करोड़ लोग साल के 170 दिनों में गंभीर धूल भरे हालात को झेलने के लिए मजबूर थे।वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि वायुमंडलीय धूल चक्र में बायोक्रस्ट की अहम भूमिका है, हालांकि इसके बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। यही वजह है कि उन्होंने इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए जलवायु में आते बदलावों और उसके बायोक्रस्ट पर पड़ते प्रभावों का अध्ययन किया है। इस शोध में जो निष्कर्ष सामने आए हैं उनसे पता चला है कि बायोक्रस्ट हर साल करीब 700 टेराग्राम धूल को वातावरण में फैलने से रोक रही है। अनुमान है कि यदि यह परत न हो तो वातावरण में 55 फीसदी ज्यादा धूल उत्सर्जित होगी।वहीं जलवायु मॉडल की मदद से किए विश्लेषण में सामने आया है कि यदि वैश्विक तापमान में होती वृद्धि जारी रहती है तो 2070 तक बायोक्रस्ट को जितना नुकसान होगा उसके चलते 15 फीसदी ज्यादा धूल उत्सर्जित हो सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी माना है कि वैश्विक रूप से धूल के उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि का पृथ्वी पर क्या परिणाम हो सकता है, या फिर किन स्थानों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि पिछले शोधों से पता चला है कि वातावरण में बढ़ती धूल सौर विकिरण को बिखेर देती है। साथ ही यह बर्फ और बादलों को बनने में भी अहम भूमिका निभाती है। इतना ही नहीं धूल के यह कण पोषक तत्वों को अपने साथ दूर तक ले जा सकते हैं। वहीं कुछ मामलों में इनके जरिए बैक्टीरिया और वायरस को भी दूसरे स्थानों तक ले जाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं।

पर्यावरणविद बनकर जागरूकता लाने के साथ पा सकते रोजगार

झांसी। अगर आप पर्यावरण को लेकर समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान कोर्स करने का बेहतरीन मौका है। बीयू में 10 जून तक आवेदन खुले हैं। पर्यावरणविद का कार्य शोधपरक होता है। इसमें प्रशासनिक, सलाहकार व पर्यावरण संरक्षण तीनों स्तरों पर कार्य करने की संभावनाएं हैं। पर्यावरण विज्ञान मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जल व ध्वनि प्रदूषण, औद्योगिक वाहन, प्रदूषण, प्लास्टिक जोखिम को दूर करने के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी का अध्ययन है। पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के बारे में पूरा विश्व जागरूक हुआ है। इसलिए पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार की तमाम संभावनाएं हैं। बीयू के पर्यावरण विज्ञान विभाग की समन्वयक डॉ. स्मिता त्रिपाठी ने बताया कि इस कोर्स को करने के बाद सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में बायोलॉजिस्ट, केंद्र व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी नौकरी पाने का मौका रहता है। इसके अलावा खुद एनजीओ शुरू करके दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। बीयू के कई छात्रों ने ऐसा किया भी है। साथ ही रिफाइनरी, खदान, टेक्सटाइल मिल, सीमेंट उद्योग, वेस्ट ट्रीटमेंट एजेंसी में पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में रोजगार पा सकते हैं।

महामारी के दौरान भूख और गरीबी के बीच हर 30 घंटे में पैदा हुआ एक नया अरबपति- ऑक्सफैम रिपोर्ट

नई दिल्ली। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी जब सारी दुनिया कोविड-19 महामारी और उसके कारण उपजे आर्थिक संकट से जूझ रही थी और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी जद्दोजहद कर रही थी, उस बीच भी दुनिया के अमीरों की आय और यादा बढ़ रही थी। ऑक्सफेम द्वारा जारी नई रिपोर्ट से पता चला है कि महामारी के दौरान हर 30 घंटे में एक अरबपति पैदा हुआ था। वहीं, दूसरी तरफ आशंका जताई है कि इस साल हर 33 घंटे में 10 लाख की दर से और 26.3 करोड़ लोग गंभीर रूप से गरीबी का शिकार हो जाएंगें।

प्रोफिटिंग फॉम पेन नामक यह रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे शिखर सम्मेलन में ऑक्सफेम द्वारा जारी की गई है। गौरतलब है कि 22 मई से 26 मई के बीच दावोस में होने वाली इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में जलवायु परिवर्तन, कोविड संकट और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में देश के शीर्ष नेताओं के साथ-साथ दुनिया के कई बड़े व्यवसायियों के शिरकत करने की उम्मीद है। इस बारे में ऑक्सफैम इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक गैब्रिएला बुचर का कहना है कि दुनियाभर के अरबपति महामारी के दौरान अपनी किस्मत और व्यवसाय में हुई अविश्वसनीय बढ़ोतरी का जश्न मनाने के लिए दावोस पहुंच रहे हैं। पहले महामारी और फिर खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की कीमतों में हुई भारी वृद्धि उनके लिए वरदान साबित हुई है। इस बीच दशकों से गरीबी के खिलाफ चल रही जंग का परिणाम गरीबों के पक्ष में नहीं है। वहीं लाखों लोग बुनियादी जरूरतों की बढ़ती कीमतों को लेकर अपने जीवन के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया भर में 2,668 अरबपति हैं जोकि 2020 की तुलना में 563 यादा हैं। इनकी कुल संपत्ति 12.7 लाख करोड़ डॉलर है, जिसमें इस दौरान करीब 3.78 लाख करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए तो इनकी सम्पति वैश्विक जीडीपी के 13.9 फीसदी के बराबर है। इस संपति में 2000 से करीब तीन गुना वृद्धि हुई है जो तब करीब 4.4 फीसदी थी। इतना ही नहीं अमीर और गरीब के बीच की यह खाई कितनी गहरी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दुनिया की सबसे कमजोर 40 फीसदी आबादी की कुल संपत्ति से भी यादा है, जिनकी कुल आबादी करीब 310 करोड़ है। इसी तरह दुनिया के 20 सबसे अमीर लोगों की सम्पति उप सहारा अफ्रीका की कुल जीडीपी से भी यादा है। इतना ही नहीं सबसे गरीब तबके की 50 फीसदी आबादी में से यदि कोई व्यक्ति अमीर तबके के किसी एक व्यक्ति की एक साल जितनी आय कमाना चाहता है तो उसे इसके लिए 112 वर्षों तक काम करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां लोग खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान हैं और उसकी कीमते दशक के उचतम स्तर पर पहुंच गई हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008